



अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद

केंद्रीय कार्यालय- 3, मार्बल आर्च, सेनापती बापट मार्ग, माटुंगा रोड (प.रे.), माहिम, मुंबई - 400016.
दूरभाष : (022) 24306321 / 24378866 फैक्स : 24313938 ई-मेल : abvpkendra@gmail.com

दिनांक: 8 अक्टूबर 2021

-: प्रेस विज्ञप्ति :-

प्रवेश परीक्षा अथवा अंकों का मानकीकरण हो डीयू में प्रवेश का आधार: अभावपि

ग्रामीण क्षेत्रों एवं आम छात्रों के हितों को लेकर किया दिल्ली विवि प्रशासन का पुतला फूंक ज़ोरदार प्रदर्शन।

ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को डीयू प्रवेश प्रक्रिया में न्याय मिले इस हेतु अभावपि ने दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन का पुतला फूंक ज़ोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की मुख्य माँगों में बढ़ी हुई कट-ऑफ को ठीक करना, नामांकन प्रक्रिया में राजकीय बोर्ड के नंबर को नॉर्मलाइज करके दाखिला दें, तत्काल प्रभाव से नामांकन प्रक्रिया को रोका जाए, नामांकन हेतु छात्रों की प्रारंभिक स्क्रीनिंग कराई जाए।

ध्यान हो कि दिल्ली विश्वविद्यालय ने 1 अक्टूबर को सत्र 2021-22 के नामांकन हेतु पहली कट ऑफ जारी की थी जिसमें पिछले वर्षों की तुलना में अनियमित उछाल देखा गया। परिणाम स्वरूप 99 प्रतिशत अंक पाने वाले छात्र भी हिंदू, हंसराज, रामजस जैसे देश के प्रतिष्ठ महाविद्यालयों में दाखिले से वंचित रह गए। इस 100 प्रतिशत वाले कट ऑफ के कारण सबसे ज्यादा नुकसान सुदूर ग्रामीण इलाकों से आने वाले उन छात्रों को हुआ है जो पूरे साल दिल्ली विश्वविद्यालय में नामांकन हेतु मेहनत करते हैं एवं सीमित अवसरों और सीमित संसाधनों के साथ अपनी पढ़ाई करते हैं। इस ऊंचे कट ऑफ के कारण केवल कुछ राज्य बोर्ड के छात्र ही दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश ले पा रहे हैं। इस भेदभावपूर्ण व्यवहार के विरुद्ध पिछले 3 दिनों से अभावपि का दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रदर्शन चल रहा है।

अभावपि प्रांत मंत्री सिद्धार्थ यादव ने कहा कि “विश्वविद्यालय के नकारेपन के कारण छात्रों का भविष्य खतरे में है। कुछ राज्यों के बोर्ड द्वारा अधिक अंक देने से देश के सभी छात्र न्याय से वंचित हैं। हम किसी एक बोर्ड या एक राज्य के विरुद्ध नहीं हैं, हमारी माँग है कि देश के सभी राज्य एवं बोर्ड के विद्यार्थियों को समान प्रवेश का अवसर मिले। दिल्ली विश्वविद्यालय को कोरोना की इस विपरीत परिस्थिति में नामांकन हेतु कोई दूसरा विकल्प अपनाना चाहिए था।”

अभावपि की राष्ट्रीय महामंत्री सुश्री निधि त्रिपाठी ने छात्रों को सम्बोधित करते हुए कहा कि “दिल्ली विश्वविद्यालय की विशेषता डीयू की विविधता है लेकिन इस कट ऑफ के कारण गांव, कस्बों से आने वाले आम छात्र नामांकन से वंचित रह जायेंगे और डीयू की विविधता खत्म हो जाएगी, और केवल वही छात्र डीयू आ पाएंगे जिनके पास संसाधन और अवसर अधिक होंगे। इसलिए प्रशासन को इसके लिए तत्काल प्रभाव से इसका समाधान करना चाहिए ताकि ग्रामीण परिवेश के छात्रों को न्याय मिल सके। हमारी माँग है कि या तो छात्रों का स्क्रीनिंग टेस्ट कराया जाए या फिर अंकों का मानकीकरण किया जाए।

(यह प्रेस विज्ञप्ति केन्द्रीय कार्यालय मंत्री सुमित पाण्डेय द्वारा जारी की गई है।)